'अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम' और 'सच्चर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन' के विभिन्न मुद्दों का प्रचार करने वाली सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों द्वारा चलाए गए प्रचार पर की गई कार्रवाई नोट

जुलाई-सितंबर 2020

<u>पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)</u>

- पीआईबी प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम और सच्चर समिति की सिफारिशों के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से विज्ञप्तियां/फीचर जारी करता है ।
- इसके विभिन्न क्षेत्रों से इस विषय पर 245 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं।

<u>लोक् सम्पर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)</u>

➢ ***प्रिंट विज्ञापन***

- ब्यूरो अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित विषयों पर अखिल भारतीय आधार पर समय-समय पर विज्ञापन जारी करता रहा है जिनमें उनके लिए उपलब्ध भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों, निधियों, छात्रवृत्तियों आदि की जानकारी दी जाती है।
- बीओसी ने तिमाही के दौरान 'छात्रवृत्ति स्कीम 2020-21' और 'भर्ती' विषय पर कई समाचार पत्रों में 3 विज्ञापन जारी किए ।

➢ ***क्षेत्र प्रचार***

- देशभर में कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, बीओसी के सभी क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो (एफओबीएस) और रीजनल लोक संपर्क ब्यूरो (आरओबीएस) ने लॉकडाउन और इससे संबंधित अनलॉक प्रतिबंधों की मौजूदा परिस्थितियों को सोशल मीडिया अर्थात फेसबुक, वाट्सऐप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि के विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन किया।

- आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों के विषय में कोविड-19, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत, होनरिंग द होनेस्ट : फेसलेस असेसमेंट ऑफ डायरेक्ट टेक्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधान मंत्री जन धन योजना, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नई शिक्षा नीति 2020 और पोषण माह सहित भारत सरकार के निर्णयों और पहलों को शामिल किया गया था।

- ब्यूरो ने देशभर में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जन समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग किया।

- सोशल मीडिया/डिजिटल कार्यकलापों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

फेसबुक पोस्ट की कुल संख्या	**ट्विट्स एवं रीट्विट्स (इंप्रेशन के साथ)**	**वाट्सएप पर परिचालित पोस्टरों/संदेश/वीडियो की कुल संख्या**	**इंस्टाग्राम पोस्ट की कुल संख्या**	**वेबीनार की कुल संख्या**
60587	**66138 (806985)**	**251608**	**10606**	**157**

- अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, पटना और पुणे के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कोविड-19 और अन्य भारत सरकार की कल्याणकारी स्कीमों पर उनके क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर मोबाइल वेन/ऑटो रिक्शा उद्घोषणा प्रचार का आयोजन किया।

<u>आकाशवाणी</u>

- सभी आकाशवाणी केंद्रों ने 'अल्पसंख्यक कल्याण' पर उपयुक्त कार्यक्रमों को तैयार करके इस विषय का व्यापक प्रचार किया ।
- विभिन्न स्वरूपों का उपयोग किया गया जिसमें- लघु चर्चा, वार्ता, साक्षात्कार, कम्पीयरिंग, स्पीच, स्पॉट, जिंगल आदि शामिल थे।
- कार्यक्रमों में मुख्यतः 15 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न घटकों और सच्चर समिति की रिपोर्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया।
- तिमाही के दौरान आकाशवाणी केंद्रों द्वारा कुल 455 कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

<u>दूरदर्शन</u>

- देश भर के विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों ने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कार्यक्रम प्रसारित किए।
- कार्यक्रमों के प्रारूप में लाइव चर्चा, फोन-इन, साक्षात्कार, पैनल चर्चा, आदि शामिल थे।
- तिमाही के दौरान दूरदर्शन केंद्रों द्वारा कुल 280 कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया ।

*****

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

जुलाई से सितंबर 2020 तक राज्य-वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का नाम	पीआईबी द्वारा जारी प्रेस रिलीज	आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की संख्या	बीओसी द्वारा प्रिंट मीडिया पर खर्च (रु. में)	डीडी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की संख्या
1	अण्डमान और निकोबार	-	-	0	-
2	आंध्र प्रदेश	16	12	15,394	-
3	तेलंगाना	-	-	28,314	-
4	अरुणाचल प्रदेश	-	-	0	-
5	असम	16	4	12,920	-
6	बिहार	14	-	66,011	-
7	चंडीगढ़	12	-		-
8	छत्तीसगढ़	4	10	51,220	5
9	मध्य प्रदेश	-	-	68,258	17
10	दादरा और नगर हवेली	-	-	0	-
11	दमन और दीव	-	-	0	-
12	गुजरात	14	141	12,920	24
13	जम्मू और कश्मीर	16	7	20,137	-
14	झारखंड	3	16	17,768	2
15	कर्नाटक	18	3	0	-
16	केरल	-	16	8,432	27
17	लक्षद्वीप	-	-	0	-
18	महाराष्ट्र	32	80	2,95,961	-
19	गोवा	-	-	15,014	-
20	मिजोरम	5	24	0	-
21	मेघालय	16	-	0	-

22	त्रिपुरा	-	24	0	-
23	नगालैंड	-	-	15,394	-
24	मणिपुर	-	3	15,394	7
25	पंजाब	-	4	1,10,501	118
26	हिमाचल प्रदेश	-	-	15,394	4
27	हरियाणा	-	-	0	1
28	दिल्ली	16	-	2,20,882	-
29	ओडिशा	-	13	58,766	9
30	पुडुचेरी	-	-	0	-
31	राजस्थान	16	-	2,20,932	6
32	तमिलनाडु	-	30	10,701	-
33	उत्तराखंड	22	-	24,255	-
34	उत्तर प्रदेश	9	68	84,071	60
35	पश्चिम बंगाल	-	-	46,382	-
36	सिक्किम	16	-	12,920	-

***